

अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 07.10.2024 को आयोजित 70वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवृत्त।

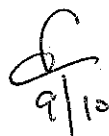
MINUTES OF THE 70th AUTHORITY MEETING HELD ON 07.10.2024 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER/CHAIRPERSON, SEEPZ-SEZ AUTHORITY.

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

The following were present:-

- | | | | |
|--|------------|--|----------------------|
| 1. श्री सी.पी.एस. चौहान,
जेडीसी, सीपज़ एसईजेड | सदस्यसचिव/ | 1. Shri C.P.S Chauhan,
JDC,SEEPZ SEZ | Member/
Secretary |
| 2. श्री हिमांशु धर पांडे, उप
निदेशक, विदेश
व्यापार महानिदेशालय के
नामिती | सदस्य | 2. Shri. Himanshu
Dhar Pandey, Dy.
Director, Nominee
of Addl. Director
General of Foreign
Trade, Mumbai | Member |
| 3. श्री. हसमुखभाई ढोलकिया, मेसर्स
एच.के.
डिजाइन (इंडिया) एलएलपी के
पार्टनर | सदस्य | 3. Shri. Hasmukhbhai
Dholakiya, Partner
of M/s. H. K. Design
(India) LLP | Member |
| 4. श्री सपिंदर सिंह, प्रबंध निदेशक,
मेसर्स
ओमेगा प्रोडक्ट्स प्राइवेट
लिमिटेड। | | 4. Shri. Sapinder
Singh,
Managing Director
of
M/s. Omega Products
Pvt. Ltd. | Member |

विशेष आमंत्रित:-	Special Invitee:-
डॉ. प्रसाद वरवंतकर, डीडीसी, सीपज़-सेज़, श्रीमती रेखा नायर, एडीसी (वित्त), श्री मनीष कुमार, एडीसी (संपदा संचालन), श्री रवींद्र कुमार, सहायक और श्री राजेश कुमार, यूडीसी भी बैठक में सहायता और सुचारु संचालन के लिए उपस्थित हुए।	Dr. Prasad Varwantkar, Estate Officer, DDC, SEEPZ SEZ, Smt. Mangala, Sr. PAO, Smt. Rekha Nair, ADC (Finance), Shri. G.S. Bhandari, ADC [Mega CFC] Shri. Manish Kumar, ADC (Estate Operations), Shri. Palash Kumar, ADC [Eviction & Recovery] & Shri Hanish Rathi ADC [Security] also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.
कार्यसूची मद सं 1 :- दिनांक 20.08.2024 को आयोजित 69वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	Agenda Item No. 1:- Confirmation of the Minutes of the 69 th Authority meeting held on 20.08.2024.
	Decision: After deliberation, the Authority confirmed the Minutes of the meeting held on 20.08.2024 with consensus with the following


9/10

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ सर्वसम्मति से **20.08.2024** को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की:

(ए) एडीसी (सुरक्षा) यूनिट के मालिक को एक विशेष वाहन पास देने के संबंध में सभी यूनिटधारकों को एक परिपत्र जारी करेगा।

(बी) पीएओ यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन से काटे गए एचआरए की भरपाई पीएफएमएस में उचित प्रक्रिया अपनाकर और अधिकारियों के कर लाभों को प्रभावित किए बिना प्राधिकरण निधि में की जाए।

(सी) सभी एजेंडे जहां "कार्रवाई" अभी भी लंबित है, कार्रवाई पूरी होने तक अगली प्राधिकरण बैठक से पहले रखी जानी चाहिए।

observations :

- ADC (Security) to issue a circular to all Unitholders regarding granting a special vehicle pass to the owner of the unit.
- PAO to ensure recoupe of HRA of govt. staff deducted from their salary to Authority fund by undertaking due process in PFMS and without affecting the tax benefits of the officers.

All agenda where "Action taken" is still pending should be placed before next Authority meeting till the action is complete.

कार्यसूची मद सं 1 .- क-: अग्रदाय के माध्यम से किया गया मासिक विवरण व्यय।
माह अगस्त, 2024 एवं सितम्बर, 2024 तक किये गये व्यय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि तत्काल आवश्यकता के कारण प्राधिकरण निधि से किए गए भारत सरकार से संबंधित सभी खर्चों को मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर संबंधित बजट प्रमुखों से प्राधिकरण निधि में वापस कर दिया जाएगा।

Agenda Item No. 1A:- Monthly Statement Expenditure incurred through Imprest.

The expenses incurred from the month of Aug., 2024 & Sept. 2024 were presented before the Authority.

It was also apprised to the Authority that all the expenses pertaining to GoI done from the authority fund due to urgent requirement shall be recouped from the concerned budget heads to Authority Fund on receipt of Sanction Order.

निर्णय:

विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने अग्रदाय के माध्यम से किए गए खर्चों को नोट किया और निर्णय लिया कि भारत सरकार के बजट से प्राधिकरण निधि में वसूली में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।

Decision:

After deliberation, the Authority noted the expenses incurred through Imprest and also directed to expedite recoupe from Gol budget to Authority Fund.

कार्यसूची मद सं 2 .: NEST 2 में लीज रेंट निर्धारण एवं अन्य नवीन आवंटन हेतु प्रस्ताव।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, एसडीएफ-1 में कुछ इकाइयों को NEST 1 में गला आवंटित किया गया है और वर्तमान में SDF-1 में मौजूद शेष इकाइयों को NEST 2 में 4500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पुनः आवंटित किया जाएगा। शेष इकाइयों को समायोजित करने पर, SEEPZ-

Agenda Item No. 2:- Proposal for fixation of lease rent in NEST 2 and for other new allotments. Authority was apprised that, some of the Units in SDF-I have been allotted galas in NEST 1 and balance Units presently occupied in SDF-I will be re-allocated to NEST 2 @ Rs. 4500/- per sq. mtr. p.a. On accommodating the balance units, SEEPZ-SEZ Authority has vacant



<p>SEZ प्राधिकरण के पास पात्र/योग्य उद्यमियों को आवंटित करने के लिए रिक्त स्थान/गालाएँ हैं। नवनिर्मित भवन में जगह की भारी मांग है।</p> <p>एनईएसटी 2 नवनिर्मित भवन है और प्राधिकरण ने निर्माण पर भारी लागत खर्च की है और निर्माण लागत को वसूलने के लिए और बाजार दर को ध्यान में रखते हुए किराए को अंतिम रूप देने की जरूरत है।</p> <p>यह भी अवगत कराया गया कि सरकारी पट्टे वाले परिसरों में भविष्य के सभी आवंटन [स्व-वित्तपोषित भवनों के अलावा] एनईएसटी 02 के लिए प्रस्तावित समान संशोधित पट्टा किराया पर लगाया जाएगा।</p>	<p>spaces/galas to be allotted to eligible/deserving entrepreneurs. There is huge demand for space in the newly constructed building. NEST 2 is newly constructed building and Authority had incurred huge cost for construction and in order to recoupe the construction cost and taking into consideration the market rate rent needs to be finalized.</p> <p>It was also apprised that all the future allotment in govt. leased premises [other than self financed buildings] to be levied at the same revised lease rent as proposed here for NEST 02.</p>
<p>निर्णय:</p> <p>विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि NEST-02 में आवंटित किए जाने वाले नए उद्यमियों को NEST-02 की निर्माण लागत की भरपाई के लिए प्रति वर्ष 6500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टा किराया लगाया जाएगा और सभी नए आवंटन पुराने भवनों (सरकारी भवन) में किए जाएंगे। प्रति वर्ष 6500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भी शुल्क लगाया जाएगा।</p> <p>प्राधिकरण ने आगे निर्णय लिया कि नियम 74 ए के तहत प्राप्त किसी भी प्रस्ताव/आवेदन या स्व-वित्तपोषित भवनों में संपत्तियों और देनदारियों को संभालने के लिए अन्य माध्यमों जैसे बैंकों/डीआरटी/परिसमापक आदि द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन। SEEPZ SEZ में उच्चतम किराये के 10% की दर से लगाया जाएगा जो वर्तमान में 650/- रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है।</p>	<p>Decision:</p> <p>After deliberation, the Authority decided that in order to recoupe the construction cost of NEST-02 lease rent @ Rs. 6500 per sq. mtr. per year to the new entrepreneurs to be allotted at NEST-02 will be levied and all new allotments in old buildings (govt. bldg) will also be levied at the rate of Rs. 6500/- per sq. mtr. .p.a.</p> <p>Authority further decided that any proposals/applications received under Rule 74 A or change of ownership by other means viz auction by Banks/DRT/ Liquidator etc. for taking over assets and liabilities in self financed bldgs. would be levied at the rate of 10% of the highest rent in SEEPZ SEZ which is at present Rs. 650/- per sq. mtr. p.a.</p>
<p>कार्यसूची मद सं3 :- एसईजेड नियम 2006 के नियम 74 ए के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों के लिए तंत्र से संबंधित शुल्क लगाने का प्रस्ताव।</p> <p>प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, कई इकाइयों ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 74ए के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है।</p> <p>नियम 74 ए के तहत एक इकाई स्थापित करने के लिए उपरोक्त नियम प्रावधान के संदर्भ में, डेवलपर से एनओसी या आशय पत्र वांछनीय है, हालांकि यह नई इकाइयों के लिए अनिवार्य है।</p>	<p>Agenda Item No. 3:- Proposal for levy of charges related to applications received for transfer of assets and liabilities under Rule 74 A of SEZ Rules 2006.</p> <p>Authority was apprised that, many units have applied for transfer of assets and liabilities under Rule 74A of SEZ Rules 2006. In terms of the aforesaid Rule provision for setting up a unit under Rule 74 A, NOC from Developer or letter of intent is desirable though it is mandatory for new Units.</p> <p>It is suggested that charges may be levied for the proposals thus</p>

2/10

<p>यह सुझाव दिया गया है कि एसईजेड नियम 2006 के नियम 74 ए के तहत प्राप्त प्रस्तावों के लिए शुल्क लगाया जा सकता है और नियम 74 ए के तहत लेनदेन के लिए अनिवार्य प्राधिकरण से एनओसी को मामले में विचार और निर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है।</p>	<p>received under Rule 74 A of the SEZ Rules 2006 and NOC from Authority mandatory for transaction under Rule 74 A is placed before the Authority for consideration and a decision in the matter</p>
<p>निर्णय:</p> <p>विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निर्णय लिया गया कि एसईजेड नियम 2006 के नियम 18 2(ii) के अनुसार, नियम 74 ए के तहत अनुमोदन प्राप्त करने वाले किसी भी आवेदक को प्राधिकरण से एनओसी प्रदान करने की आवश्यकता है। साथ ही वित्तीय संस्थानों, एनसीएलटी, डीआरटी आदि से बिक्री प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली इकाइयों को भी प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता है। उपरोक्त के अलावा, ऐसे प्रस्तावों पर लेनदेन लागत/परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के प्रशासनिक शुल्क पर न्यूनतम 3% लगाया जाना चाहिए।</p>	<p>Decision:</p> <p>After deliberation, the Authority decided that in terms of Rule 18 2(ii) of the SEZ Rules 2006, any applicant obtaining approval under Rule 74 A need to provide NOC from Authority. Also Units obtaining Sale certificate from financial institutions, NCLT, DRT etc. also need to obtain NOC from Authority.</p> <p>In addition to the above, such proposals to be levied minimum 3% towards administrative charges of the transaction cost/valuation of assets.</p>
<p>कार्यसूची मद सं 4 :- मेगा सीएफसी के अधिकृत संचालन से परे स्थान के उपयोग और जीजेईपीसी और एसईईपीजेड प्राधिकरण के बीच राजस्व साझेदारी के लिए जीजेईपीसी और एसईईपीजेड प्राधिकरण के बीच समझौते का प्रस्ताव।</p> <p>प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, जीजेईपीसी ने सरकारी और निजी संस्थाओं को कार्यक्रमों के लिए जगह प्रदान करने के लिए ग्राउंड, 5वीं और 6वीं मंजिल पर मेगा सीएफसी की जगह का उपयोग करने की इच्छा जताई है क्योंकि यह मेगा सीएफसी यूनिट के रूप में उनके अधिकृत संचालन के तहत कवर नहीं किया गया है। इसके अलावा, एसईजेड प्राधिकरण उक्त क्षेत्र का सही ढंग से उपयोग/किराए पर दे सकता है और इसलिए जीजेईपीसी सकल संग्रह पर 75:25 मॉडल के राजस्व बंटवारे का प्रस्ताव लेकर आई है, जहां करों को छोड़कर सभी खर्च जीजेईपीसी द्वारा वहन किए जाएंगे।</p>	<p>Agenda Item No. 4:- Approval of MOU between GJEPIC & SEEPZ Authority for utilization of vacant space at Mega CFC beyond Authorized operations of GJEPIC unit at Mega CFC on revenue sharing basis.</p> <p>Authority was apprised that, the GJEPIC have desired to utilise the space of Mega CFC at Ground, 5th & 6th floor to offer space for events to Govt & Pvt. entities as the same is not covered under their authorised operations as a Mega CFC Unit. Further, SEZ Authority can rightly use / rent out said area and therefore GJEPIC have come up with a proposal for revenue sharing of 75:25 model on gross collection where all expenses, except taxes will be borne by GJEPIC.</p>
<p>निर्णय</p> <p>: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि लागू करों को छोड़कर सकल आधार पर 75:25 के अनुपात में राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर अपने अधिकृत संचालन के अलावा भूतल, 5 वीं और 6 वीं मंजिल पर स्थान के उपयोग के लिए जीजेईपीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एमओयू के प्रारूप को मंजूरी दी गई। प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि एस्करो बैंक खाता प्राधिकरण द्वारा बनाए रखा जाएगा और बिल/चालान प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे। जीजेईपीसी द्वारा प्राप्त आय</p>	<p>Decision:</p> <p>After deliberation, the Authority approved the proposal of GJEPIC for utilization of space at ground floor, 5th & 6th floor in addition to their authorized operation on revenue sharing basis in the ratio of 75:25 on gross basis except applicable taxes. The draft MOU was approved. Authority also directed that the Escrow bank account will be</p>

(Handwritten signature)

<p>का उपयोग केवल मेगा सीएफसी के लिए किया जाएगा।</p>	<p>maintained by Authority and bills/invoices will be raised by Authority. The income by GJEPC to be utilized for Mega CFC only.</p>
<p>कार्यसूची मद सं5 .:- सोशल मीडिया के लिए 01 जनसंपर्क अधिकारी और एक अंशकालिक संसाधन कार्यकारी की नियुक्ति।</p> <p>प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार SEEPZ प्राधिकरण द्वारा बहुत सारी गतिविधियाँ और कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न सरकारों के साथ आवश्यक समन्वय आवश्यक है। ऐसे आयोजनों के सुचारु संचालन के लिए लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभाग और अन्य संगठन। इसलिए 50000 रुपये से 60000 रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक के साथ एक योग्य/अनुभवी जनसंपर्क अधिकारी और 20000 रुपये से 25000 रुपये के पारिश्रमिक के साथ हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में SEEPZ के बारे में मीडिया को संभालने के लिए एक संसाधन की आवश्यकता है।</p>	<p>Agenda Item No. 5 Hiring of 01 Public Relation Officer and one part time Resource Executive for Social Media.</p> <p>Authority was apprised that, there are lot of activities and events being carried out by SEEPZ Authority as per the instructions of Ministry for which necessary co-ordination is required with various govt. departments and other organizations for logistics as well as other arrangements for smooth operations of such events. Hence there is a need to hire a qualified/experienced Public Relation Officer with a remuneration of Rs. 50000 to Rs. 60000 per month and one Resource for handling media regarding SEEPZ in Hindi, English & Marathi with a remuneration of Rs. 20000-Rs. 25000.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने प्रोटोकॉल अधिकारी और एक संसाधन कार्यकारी के पद पर एक संसाधन को काम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में अच्छी तरह से मसौदा तैयार करने में सक्षम हो और हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में अच्छा संचार कौशल रखता हो और किसी भी प्रारूप का मसौदा तैयार कर रहा हो। लेख और सोशल मीडिया पर अपलोड करना।</p>	<p>Decision: After deliberation, Authority approved the proposal for hiring of one resource in the designation of Protocol Officer and one resource executive who is well conversant with Hindi, English & Marathi the drafting and having good communication skills in Hindi, English & Marathi language and, drafting any article and uploading on social media.</p>
<p>कार्यसूची मद सं6 .:- SEEPZ-SEZ में मेसर्स रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से कैपेक्स फाइबर बिछाने के काम के लिए वाणिज्यिक कोटेशन प्राप्त करने का प्रस्ताव।</p> <p>प्राधिकरण को सूचित किया गया कि फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना कई कारणों से आवश्यक है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और निर्यात-उन्मुख व्यवसायों पर क्षेत्र के फोकस को देखते हुए। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ एकीकृत फाइबर नेटवर्क बड़े प्रतिस्थापन की आवश्यकता के बिना उच्च गति और अधिक कनेक्शन को समायोजित कर सकता है, जिससे SEEPZ इकाइयों को अपनी कनेक्टिविटी आवश्यकताओं का विस्तार करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा जोन में गटर पाइपलाइन वर्षों पहले अनुचित तरीके से स्थापित फाइबर नेटवर्क केबलों के कारण अवरुद्ध हो रही हैं और फाइबर नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे रखरखाव और स्थापना करना मुश्किल हो गया है।</p>	<p>Agenda Item No. 6:- Proposal for obtaining Commercial quotation for Capex Fibre laying work from M/s RailTel Corporation of India Limited at SEEPZ-SEZ.</p> <p>Authority was informed that Laying fibre optic cables is essential for several reasons, especially considering the zone's focus on technology and export-oriented businesses. With advancement of technology the integrated fibre network can accommodate higher speeds and more connections without the need for major replacements, allowing SEEPZ units to expand their connectivity needs. Further gutter pipelines in the zone are getting choked due to fibre network cables improperly installed years ago and there is no enhancement in the fibre network which make it difficult</p>


 09/10

	for maintenance & installation.
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने कैपेक्स फाइबर बिछाने के काम के लिए वाणिज्यिक कोटेशन प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।	Decision: After deliberation, the Authority approved the proposal for obtaining Commercial quotation for Capex Fibre laying work.

उपरोक्त एजेंडे के अलावा, व्यापार सदस्य में से एक ने उल्लेख किया था कि नालियां बुरी तरह से जाम हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप यूनिट में सीवेज का पानी जमा हो गया है और यह कर्मचारियों के लिए अस्वच्छ हो गया है। प्राधिकरण द्वारा एडीसी (एस्टेट) को परिसर का दौरा करने और तुरंत अनुपालन में भाग लेने और ठेकेदार को गंदगी साफ करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया था।

In addition to the above agendas, one of the Trade Member had mentioned that the gutters are badly choked up which has resulted in sewage water getting clogged in the Unit and making it unhygienic for the employees. ADC (Estate) was directed by the Authority to visit the premises and attend to the complaint immediately and instructing the contractor to clear the chock up.

व्यापार सदस्य ने एमआईडीसी और उसके ठेकेदारों के माध्यम से गेट नंबर 2 के काम में तेजी लाने की भी बात कही। प्राधिकरण ने उक्त अनुरोध को नोट किया और आश्वासन दिया कि काम तेजी से किया जाएगा।

Trade member also pointed out to expedite the work of Gate no. 2 through MIDC and its contractors. Authority noted the said request and assured that the work will be taken up speedily.

यह भी अवगत कराया गया कि गेट नं. 1 रात के दौरान 12.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक बंद रहता है और रात की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों को सुबह 5.00 बजे के बाद ही जोन छोड़ने की अनुमति होती है। प्राधिकरण ने इस पर ध्यान दिया और सुरक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रचलित परिपत्र के निर्देशों का पालन किया जाए।

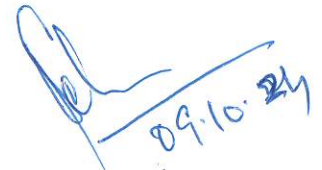
It was also apprised that the gate no. 1 is closed during night hours beyond 12.00 a.m. till 5.00 a.m. and employees working in night shifts are permitted to leave the Zone only after 5.00 a.m. Authority took note of the same and instructed Security Officer to ensure that the directions of the prevailing circular to be adhered to.

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

The meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

यह सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Chairperson, SEEPZ SEZ Authority.


09.10.24

(सी.पी.एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़ सेज़,

सदस्य/सचिव